छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार
शहीदों की
जनता से रिश्ता

चीन का बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमा आर्थिक गलियारा परियोजना छोड़ने से इनकार : बीजिंग। चीन ने सोमवार को इस बात से इनकार किया कि उसने बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमा (बीसीआईएम) आर्थिक गलियारा को अपने अरबों डालर के क्षेत्र और सड़क पहल (बीआरआई) से हटा दिया है। ऐसी रिपोर्ट थी कि भारत और चीन के बीच चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को लेकर मतभेद के कारण बीसीआईएम परियोजना में कम प्रगति को देखते हुए चीन ने बीआरआई से इसे हटा दिया है। बीसीआईएम 2013 में शुरू बीआरआई का हिस्सा रहा है। अप्रैल में दूसरे क्षेत्र एवं सड़क मंच की बैठक दौरान 35 गलियारों की सूची में इसका नाम नहीं था।

सराफा बाजार भाव

रायपुर

सोना	₹ 33,460	10 ग्राम
चांदी	₹ 39,600	किलोग्राम

मुंबई

सोना	₹ 33,416	10 ग्राम
चांदी	₹ 36,719	किलोग्राम

लंदन

सोना	₹ 30,191	10 ग्राम
चांदी	₹ 37,303	किलोग्राम

एनएससी निफ्टी

बीएसई सेंसेक्स

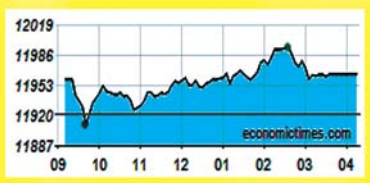

ताजा खबर

संक्षिप्त

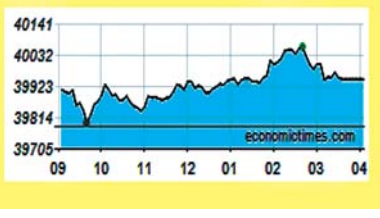

फ्रांस भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए सात लाख यूरो देगा

बर्न/नई दिल्ली (ए.)। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) ने सोमवार को फ्रांसीसी राष्ट्रीय रेलवे (एसएनसीएफ) और फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है जिसके तहत भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते सात लाख यूरो का अनुदान दिया जाएगा। इस समझौते पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी, यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांस के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमॉयने, भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जीग्लर और फ्रांस दूतावास तथा भारतीय रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

अमेरिका का टैरिफअस्त्र नाकाम! चीन के निर्यात में हुई बढ़त

चीन के निर्यात में हुई बढ़त चीन के निर्यात में हुई बढ़त।

नई दिल्ली (ए.)। चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है कि अमेरिका के सख्त टैरिफ थोपने के बावजूद चीन के निर्यात में बढ़त हुई है। मई महीने में चीन का निर्यात 1.1 फीसदी बढ़ा है, जबकि इसमें गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही थी, क्योंकि अमेरिका ही चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि, इस दौरान चीन का आयात घटा है, जो इसका संकेत है कि घरेलू मांग में कमी आ रही है।

निर्यात में तेज बढ़त के बारे में कुछ जानकारों का कहना है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ थोपने की समय सीमा से पहले बहुत से निर्यातकों ने तेजी से अपना माल निर्यात करना शुरू किया, जिसकी वजह से यह बढ़त दिख रही है।

हालांकि, न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक चीन के निर्यात बढ़ने के बावजूद इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर चली जाएगी।

जानकारों का कहना है कि चीन के आयात में कमी को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे अपने बाजारों को सहारा देने के लिए राहत पैकेज देना पड़ेगा। चीन के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 20 फीसदी हिस्सा निर्यात का होता है। चीन के आयात में 8.5 फीसदी की गिरावट आई है जो पिछले तीन साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने गत 10 मई को 200 अरब डॉलर के चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया था और बाकी बचे 300 अरब डॉलर की वस्तुओं पर भी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया था। ट्रम्प इस महीने जी-20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे लेकिन जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल किसी समझौते की उम्मीद कम ही लग रही है। दोनों देशों के बीच खाई काफी बढ़ गई है। चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा में सचेत रहने को कहा है, तो अमेरिकी सांसदों ने चीनी स्टुडेंट्स के लिए वीजा नियम सख्त बनाने की मांग की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नूशिन ने शनिवार को कहा कि अमेरिका व्यापार विवाद में चीन के साथ आगे और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह के संभावित करार के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को इस माह के अंत में होने वाली बैठक तक इंतजार करना होगा। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार पिछले साल मार्च से चल रहा है, जब ट्रम्प प्रशासन ने चीन से आयात होने वाले स्टील और अल्युमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में तब चीन ने भी अरबों डॉलर के अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ा दिया था। चीन असल में थोड़ा दबाव में इसलिए रहा क्योंकि यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका ही चीन का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

TCS बनी देश की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप में RIL को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली (ए.)। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेस (TCS) सोमवार को मार्केट वैल्यू के मामले में भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई। टीसीएस ने मामूली अंतर से रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को पीछे छोड़ा। शेयर के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर टीसीएस की मार्केट वैल्यू 8.37 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि आरआईएल की मार्केट वैल्यू 8.36 लाख करोड़ रुपए रही।

टीसीएस का शेयर 2.39 फीसदी मजबूत : ट्रेडिंग सेशन के अंत में बीएसई पर टीसीएस का शेयर 2.39 फीसदी की मजबूती के साथ 2,231.10 रुपए पर बंद हुआ, वहीं आरआईएल का शेयर 0.27 फीसदी की मामूली तेजी के साथ 1,318.85 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पिछले महीने ही आरआईएल ने कायम की थी बादशाहत

पिछले एक डेढ़-दो माह में थोक भाव में आई तेजी

अरहर की दाल के दाम 100 रुपये के पार

एजेंसी

नई दिल्ली । अरहर की दाल के खुदरा दाम सौ रुपये के पार पहुंच गए हैं। पिछले एक डेढ़-दो माह में थोक भाव में आई तेजी से यह उछाल दिखा है। अगर मानसून सामान्य नहीं रहता है तो दालों खासकर अरहर के दाम फिर आसमान छू सकते हैं। अरहर दाल बाजार और मॉल में 100 से 120 रुपये किलो तक के दाम में बिक रही है। मंडी विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो माह में थोक दाम में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई है। लेमन तुअर 5850 तक और अरहर दड़ा 7300 रुपये तक पहुंच गई है। दाल पटका 7600 से 8200 रुपये प्रति क्विंटल तक है। उनका कहना है कि मानसून सामान्य रहने की संभावनाओं से पिछले एक हफ्ते में थोक दाम थोड़ा गिरे भी हैं, लेकिन खुदरा विक्रेताओं ने दाम नहीं घटाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दालों का दाम ऊंचा है। दालों के बड़े उत्पादक देश म्यांमार में भी फसल इस बार आधी रही है। उनका कहना है कि उड़द की नई फसल सितंबर में आएगी और अरहर की नई फसल तो दिसंबर-जनवरी तक नहीं आनी है, ऐसे में कीमतों में तेजी आगे भी कायम रह सकती है।

किसानों ने कम बुवाई की : विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों से दाम में नरमी रहने के कारण किसानों ने कम रकबे में दाल की बुवाई की। रकबे के हिसाब से उत्पादन भी कम रहा और कीड़े लगने से भी काफी बड़े इलाके में फसल चौपट हो गई। इससे अरहर की पिछली रबी और खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ। दिसंबर-जनवरी की महाराष्ट्र और कर्नाटक की पैदावार तो बेहद खराब रही। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी उत्पादन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

मानसून सामान्य न रहा तेज उछाल आएगा : विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मानसून सामान्य नहीं रहा तो लगातार दूसरे साल दालों का फसल चक्र प्रभावित होगा। इससे उत्पादन कम होगा और अरहर समेत सभी दालों में तेजी का रुख रहेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज्यादातर इलाके पहले ही जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो फिर वही स्थिति आ सकती है, जब अरहर के दाम 200 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गए थे। इसके बाद मोजाम्बिक और अन्य देशों से दाल का भारी निर्यात करना पड़ा था।

सरकार के गलत हस्तक्षेप से नुकसान: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के बाजार में गलत समय पर हस्तक्षेप से नुकसान होता है। सरकार ने ऊंचे भाव के दौरान 90 रुपये में बाजार से दाल खरीदी और फिर नेफेड के माध्यम से 30 रुपये में बेच दी। मसूर और चना भी इस तरह सस्ता बेचा गया। इससे बाजार बिगड़ता है। दाम तेजी से नीचे गिरते हैं तो किसानों को नुकसान होता है और उछाल आता है तो वह अगले साल बंपर उत्पादन को प्रेरित होता है, जिससे फिर दाम औंधे मुंह गिरते हैं।

सात माह के उच्चतम स्तर पर रहेगी महंगाई : गर्मी के मौसम में सब्जियों, दालों के दाम में तेज उछाल से खुदरा महंगाई मई में तीन का आंकड़ा पार कर सकती है। 3.1 फीसदी के साथ इसके सात माह के उच्चतम स्तर पर रहने की संभावना है, जो अप्रैल में 2.92 फीसदी रही थी।

हालांकि यह आरबीआई के चार फीसदी के लक्ष्य से काफी कम है और पहली छमाही तक चिंता की बात नहीं है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई चार फीसदी के आसपास पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च से खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल प्री-मॉनसून की बारिश करीब 22 फीसदी कम हुई है। मानसून में देरी से बुवाई भी देरी से होगी, जिसका आगे भी असर दिखेगा।

कमिश्नर रैंक के 12 आयकर अधिकारियों को बर्खास्त किया

एक्शन : भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई

पद का दुरुपयोग करने और गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति अर्जित करने के थे आरोप।

नई दिल्ली (ए.)। सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनमें कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस सूची में शामिल एक बर्खास्त जॉइंट कमिश्नर के खिलाफ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं।

नोएडा में तैनात यौन उत्पीड़न के आईआरएस अधिकारी को हटाया

सूत्रों ने बताया कि इसमें नोएडा में तैनात आयुक्त (अपील) पद के एक आईआरएस अधिकारी भी है। उस पर आयुक्त स्तर की दो महिला आईआरएस अधिकारियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 3.17 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी।

यह संपत्ति कथित तौर पर पद का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट एवं गैर-कानूनी तरीकों से अर्जित की गई थी। इस अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का निर्देश दिया गया है। आयकर विभाग के एक कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आय से अधिक का मामला दर्ज किया था और उन्हें अक्टूबर 2009 में सेवा से निलंबित कर दिया था। उन्हें भी सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्त लेने के लिए कहा है।

गलत आदेशों के जरिए वसूली करता था अधिकारी

एक अन्य अफसर जो भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में लिप्त था और कई गलत आदेश पारित किए थे। इन आदेशों को बाद में अपीलीय प्राधिकरण ने पलट दिया था। उसे भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। कमिश्नर रैंक के एक अन्य अधिकारी पर मुखौटा कंपनी के मामले में एक व्यवसायी को राहत देने के एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसके अलावा उसने पद का दुरुपयोग करके चल/अचल संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा था। उसे भी जबरिया सेवानिवृत्ति कर दिया गया है।

ये अधिकारी किए गए बर्खास्त

आलोक कुमार मित्र, कमिश्नर
अरुलप्पा बी, कमिश्नर ,
बीवी राजेंद्र, कमिश्नर
अजय कुमार सिंह, कमिश्नर
एसके श्रीवास्तव, कमिश्नर
होमी राजवंश, कमिश्नर
श्वेताभ सुमन, कमिश्नर
ए रविंदर, एडिशनल कमिश्नर
विवेक बत्रा, एडिशनल कमिश्नर,
चंद्रसेन भारती, एडिशनल कमिश्नर,
अशोक अग्रवाल,ज्वाइंट कमिश्नर,
राजकुमार भार्गव, असिस्टेंट कमिश्नर ।

मोदी सरकार की पेंशन स्कीम में व्यापारियों की दिलचस्पी नहीं

छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित पेंशन स्कीम को ज्यादातर व्यापारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका सबसे ज्यादा ऐतराज बेनिफिट की बेहद कम रकम, लाभार्थी की ओर से अनिवार्य मंथली योगदान और नामांकन के लिए सिर्फ 18-40 साल की उम्र सीमा को लेकर है। अभी यह भी साफ नहीं है कि स्कीम 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर तक जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए होगी या गैर-रजिस्टर्ड दुकानदारों के लिए भी। कई ट्रेड असोसिएशंस ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर स्कीम में बदलाव की मांग की है और बेनिफिट्स को टर्नओवर से जोड़ने का सुझाव भी दिया है। चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट प्रदीप गुप्ता ने कहा कि स्कीम में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें व्यापारी और सामान्य नागरिक के बीच अंतर नजर नहीं आता। इसके तहत सिर्फ 18-40 वर्ष की उम्र के लोग नामांकन करा सकते हैं, जबकि पेंशन 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलेगी। उस पर सिर्फ 3,000 रुपये की रकम, जो किसानों और मजदूरों की पेंशन योजनाओं जैसी है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इसके दायरे में वे दुकानदार भी आने चाहिए, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं। वहीं, रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए रकम बढ़नी चाहिए। सरकार चाहे तो इसे उनके टर्नओवर, टैक्स पेमेंट या रिटर्न फाइलिंग से लिंक कर सकती है। उन्होंने कहा कि अभी देश में 2 करोड़ से ज्यादा व्यापारी 50 से 60 की उम्र सीमा में हैं, जबकि 1.5 करोड़ 60 साल के करीब हैं। उन्हें भी स्कीम से जोड़ा जाना चाहिए। सरकार ने स्कीम के लिए 1.5 करोड़ की ऊपरी सीमा तो तय कर दी है, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि निचले स्तर पर कैसे तय होगा कि कोई दुकानदार है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक हलफनामा, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी मांगी गई है। ट्रेडर्स का मानना है कि यह दस्तावेज तो कोई भी मुहैया करा सकता है। बेहद छोटे दुकानदारों की भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिख रही क्योंकि उन्हें 60 साल की उम्र तक अपनी तरफ से हर महीने योगदान देना होगा।

आरबीआई ने बैंकों से कहा सुविधाएं दे

अब जीरो बैलंस बैंक अकाउंट वाले भी काट सकेंगे चेक

नई दिल्ली (ए.)। बैंक अब अपने जीरो बैलंस वाले खाताधारकों को भी चेकबुक एवं अन्य वह सुविधाएं दे सकेंगे जो एक रेग्युलर सेविंग्स अकाउंट वाले ग्राहकों को देते हैं। रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति दे दी। दरअसल, देश में नकदी लेनदेन कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत, आरबीआई ने हाल ही में आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर को नि:शुल्क कर दिया है। बहरहाल, आइए समझते हैं कि बैंकों को आरबीआई से मिली नई अनुमति से क्या बदलने वाला है...1. पहले तो यह समझना जरूरी है कि जीरो बैलंस वाले अकाउंट को ही बैंकिंग की भाषा में प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) अकाउंट कहा जाता है। इसे ही नो-फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं। 2. बीएसबीडी अकाउंट खुलवाने पर ग्राहकों को हर महीने निश्चित न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होती है।

3. ऐसे अकाउंट पर कुछ न्यूनतम सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। मसलन, जीरो अकाउंट वाले खाताधारक महीने में चार बार पैसे निकाल सकते हैं, बैंक की शाखा में पैसे जमा करा सकते हैं। यानी, महीने पैसे निकालने और जमा करने, दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कुल मिलाकर चार बार ही कर सकते हैं।

4. जीरो-बैलंस अकाउंट्स वाले को भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन, उन्हें चेकबुक जारी नहीं किया जाता।

5. आरबीआई ने बैंकों के लिए अपने जीरो बैलंस अकाउंट होल्डर्स को सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स जितनी सुविधाएं देना अनिवार्य नहीं किया है, बल्कि उन्हें अनुमति दी है। इसका मतलब है कि बैंक अगर चाहें तो नए नियम के तहत जीरो बैलंस वाले खाताधारकों को चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। साथ ही, वह महीने में चार बार जमा और निकासी की सीमा खत्म कर सकते हैं और जीरो बैलंस अकाउंट वालों को भी जितनी बार चाहे पैसे जमा कराने या निकालने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन, इसके लिए कोई फीस नहीं लगाई जा सकती है।

6. जो बैंक अपने जीरो बैलेंस वाले खाताधारकों को बचत खाता धारकों जैसी सुविधाएं अब भी नहीं देंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ध्यान रहे कि आरबीआई ने बैंकों को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया है, बल्कि ऐसा करने की अनुमति दी है। यानी, बैंक की मर्जी वह अपने जीरो बैलंस वाले खाताधारकों को ये सुविधाएं दे या नहीं।

7. आरबीआई ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि ऐसा करने वाले बैंक जीरो बैलंस अकाउंट वाले खाताधारकों से न्यूनतम राशि मेंटेन करने को नहीं कह सकते। साथ ही, वह खाता नई सुविधाओं के साथ भी बीएसबीडी अकाउंट ही रहेगा, न कि वह सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा।

8. नियमित बचत खाता (रेग्युलर सेविंग्स अकाउंट) खुलवाने पर आपको हर महीने एक निश्चित न्यूनतम रकम खाते में रखना होता है।